ed, it is not possible for State Governments to implement various welfare measures in the States including financial benefits to State employees. All India State Governments Employees' Federation made several representations in this respect to Prime Minister and the Union Finance Minister. It is a dual responsibility of both the State and Central Governments to meet the genuine demands of the State Employees. The All India State Government Employees' Federation has decided to call upon five million State employees and teachers to observe one day's nationwide token strike on September 4, 1984, and the strike notices have been served upon Central and State Governments accordingly. So, I shall urge upon the Central Government to evolve ways and means so that the following demands of the State Government employees and teachers are fulfilled :—

(1) To control price rise by effecting change in the economic policy of the Central Government and strengthening and widening of public distribution system.

2. 8.33 per cent bonus to State employees.

3. Interim relief to State employees on Central pattern and pay parity with the public sector employees.

4. Central D.A. with arrears.

5. Devolution of more funds by the Central Government to the State Governments.

6. Vacation of victimination and scraping of all anti-employees enactments by the Centre and States.

7. Full trade union and democratic rights for the State employees.

(xx) **Proposed shifting of Defence Vehicles Factory and the Grey Iron Foundry**

**श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) :** सभापति जी, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, भौगोलिक दृष्टि से, भारत का मध्य-बिन्दु है। सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण प्रतिरक्षा से सम्बन्धित अनेकों कारखाने यहां पर स्थित हैं। लगभग अस्सी हजार कर्मचारी इन सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत हैं। इनमें एक है व्हेक्ल फैक्टरी तथा दूसरा है ग्रे आयरन फाउण्डरी। पहले की स्थापना 1971 में तथा दूसरे की 1974 में हुई थी। क्रमश: 13000 तथा 4000 कर्मचारी अर्थात् कुल 17000 कर्मचारी, इनमें कार्यरत हैं।

कुछ समय से यह अफवाह फैल रही है कि इन दो सुरक्षा संस्थानों का प्रबन्ध किसी उपक्रम (अंडरटेकिंग) को दिया जाएगा और यह सम्भावना होगी कि अधिकांश कर्मचारी स्थानांतरित होंगे।

मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अर्थात् विगत 37 वर्षों में प्रतिरक्षा से सम्बन्धित 84 कारखानों में से यही दो कारखाने, जिनमें रक्षा विभाग के लिए जोंगा-जीप, शक्तिमान ट्रक, आदि की निर्मिती होती है, क्यों उपक्रम (अंडरटेकिंग) के लिए छांटे गए।

अत: मेरा रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दें। मेरी मांग यह यह है कि इन दोनों सुरक्षा संस्थानों को अथवा इनमें कार्यरत 17 हजार कर्मचारियों को जबलपुर से न हटाया जाए।